10 -02-2023

5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कॉन्ग्रेस

समाचार पत्रों में क्यों?

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पांचवीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस, आईएमपीएसी5 (जो 9 फरवरी तक कनाडा के वैंकूवर में चल रही है) को किक-ऑफ करने के लिए, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री स्टीवन गुइलबौल्ट ने एनएमसीए की स्थापना और प्रबंधन की घोषणा की, ताकि समुद्री संरक्षण प्राप्त करने की दिशा में एक पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके।

त्वरित मुद्दा?

- वर्तमान में, पार्क्स कनाडा ग्वाई हानास राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व, राष्ट्रीय समुद्री संरक्षण क्षेत्र रिजर्व और उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया तट के साथ हैदा हेरिटेज साइट जैसे पांच एनएमसीए का संचालन करता है। अन्य सात के लिए सक्रिय प्रस्तावों के साथ, मैगडलेन द्वीप समूह, जॉर्जिया के दक्षिणी जलडमरूमध्य में एनएमसीए सहित, ब्रिटिश कोलंबिया का सेंट्रल कोस्ट, लैब्राडोर का उत्तरी तट और जेम्स और हडसन बे के साथ काम कम से कम तीन अतिरिक्त उम्मीदवार साइटों की पुष्टि करने के लिए जारी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- कम-से-कम 70% MPA अंडरफंडेड हैं। एक अच्छी तरह से प्रबंधित और पर्याप्त रूप से वित्तपोषित MPA कमज़ोर पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के रूप में बहाल कर सकता है।
- टिकाऊ और लचीला MPA नेटवर्क प्राप्त करना सुरक्षा, नेतृत्त्व, हितधारकों, संस्थानों, सरकारों तथा संगठनों, स्थानीय लोगों, तटीय समुदायों एवं व्यक्तियों के साथ समावेशी व न्यायसंगत तरीके से महासागर संरक्षण को आगे बढ़ाने की समग्र प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।
- IMPAC5 का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान-प्रदान के लिये खुले और सम्मानजनक वातावरण में ज्ञान, सफलताओं एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एक मंच प्रदान करना है।
- पर्यटन कार्यक्रमों के लिये वैधानिक और गैर-सांविधिक MPA शुल्क, मैंग्रोव संरक्षण से उत्पन्न ब्लू कार्बन क्रेडिट एवं वनों की कटाई से बचने के साथ-

अन्य प्रमुख तथ्य?

IMPAC

- IMPAC कॉन्ग्रेस प्रकृति के संरक्षण के लिये अंतर्राष्ट्रीय संघ (IUCN) और चुने हुए मेज़बान देश के बीच एक सहयोगी प्रयास है।
- MPAs के प्रबंधन में नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिये कॉन्ग्रेस दुनिया भर के वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, चिकित्सकों तथा हितधारकों को एक साथ लाती है।
- IMPAC का लक्ष्य विश्व की समुद्री जैवविविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग को आगे बढ़ाना है तथा समुद्री संरक्षण एवं प्रबंधन के लिये जैविक विविधता के लक्ष्यों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन का समर्थन करना है।

साथ समुद्री शैवाल की खेती तथा टिकाऊ तटीय मत्स्यपालन से राजस्व उत्पन्न किया जा सकता है।

- MPAs महासागर के निर्दिष्ट क्षेत्र हैं जिसके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और उनकी जैवविविधता की सुरक्षा और संरक्षण किया जा रहा है।
- विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र निगरानी अथवा मत्स्य प्रबंधन संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने के लिये क्षेत्र के भीतर कुछ गतिविधियाँ सीमित अथवा पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
- MPA के तहत मछली पकड़ने, अनुसंधान और अन्य मानवीय गतिविधियों को हमेशा प्रतिबंधित नहीं किया जाता है; वास्तव में कई MPAs विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

अन्य प्रमुख तथ्य?

भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र

- भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत नामित 33 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं जो देश के MPA का निर्माण करते हैं।
- कच्छ की खाड़ी में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य एक इकाई बनाते हैं तथा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एवं भितरकनिका अभयारण्य MPA के अभिन्न अंग हैं।
- इस प्रकार भारत में कुल 31 MPA हैं।
- MPAs भारत के सभी संरक्षित क्षेत्रों के कुल क्षेत्रफल के 4.01% से कम हिस्से को कवर करते हैं।

- MPAs समुद्री प्रजातियों की विविधता और उनके आवासों को संरक्षित करने में मदद करते हैं, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं, जैसे कि भोजन और ऑक्सीजन के उत्पादन को संरक्षित करते हैं।
- MPAs मछली पकड़ने की गतिविधियों को विनियमित करने और ओवरफिशिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मछली की उचित आबादी बनी रहे ताकि सतत् मछली पालन की स्थायी प्रथाओं को सहयोग मिलता रहे।
- MPAs कार्बन सिंक के रूप में काम कर सकते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहीत करने में मदद करते हैं तथा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं।
- MPAs वैज्ञानिक अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों के लिये बहुमूल्य अवसर प्रदान कर सकते हैं, समुद्री पर्यावरण के प्रति हमारी समझ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

- MPAs पर्यटकों को आकर्षित कर स्थायी पर्यटन और मनोरंजन के अवसर प्रदान करने तथा स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों का समर्थन कर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान कर सकते हैं।
- बर्न अभिसमय:-इसे वर्ष 1979 में यूरोपीय समुदाय परिषद के तत्त्वावधान में तैयार किया गया था, यह वर्ष 1982 से लागू है और इसमें यूरोपीय राज्य शामिल हैं।

- CITES:-वर्ष 1973 में UNEP के तहत तैयार किया गया CITES वर्ष 1975 से दुनिया भर में लागू है। वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है।
- यूरोपीय संघ आवास निर्देश:-वर्ष 1992 में यूरोपीय समुदाय परिषद द्वारा तैयार किया गया यूरोपीय संघ आवास निर्देश यूरोपीय संघ के सभी राज्यों पर लागू होता है, जिसमें अज़ोरेस और मदीरा (पुर्तगाल का हिस्सा) तथा कैनरी द्वीप समूह शामिल हैं।
- अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिये आयोग (CCAMLR):;-समुद्री जीवित संसाधनों की चिंताओं के मद्देनज़र अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिये आयोग (CCAMLR) एक बहुपक्षीय प्रतिक्रिया है जो दक्षिणी महासागर के वातावरण को प्रभावित करते हुए क्रिल जैसे जीवों की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इससे भोजन के लिये क्रिल पर निर्भर रहने वाले समुद्री पक्षी, सील, व्हेल तथा मछली भी प्रभावित हो सकते हैं।

नासा – इसरो का निसार मिशन

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में पृथ्वी के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु 'नासा-इसरो 151 ब्रॉडबैंड उपग्रह'(NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar satellite -NISAR) अर्थात 'निसार' नामक एक उपग्रह मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एवं राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका के ' राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन'(नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन - NASA) द्वारा अन्तर में भेजा जा रहा है।

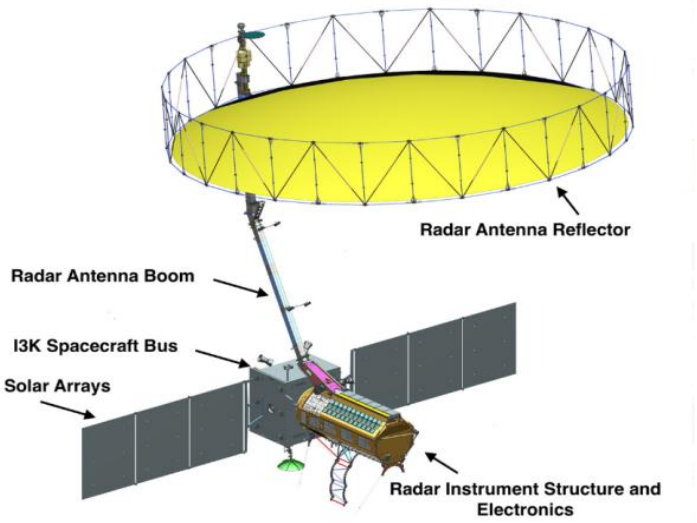

त्वरित मुद्दा?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और अमेरिका स्थित नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के नेतृत्व में एक बड़े संयुक्त मिशन पर काम चल रहा है. लगभग एक साल बाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने शक्तिशाली जीएसएलवी को लॉन्च करेगा।
- इसमें एक एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जो भूमि पर होने वाले परिवर्तनों को अभूतपूर्व विस्तार से ट्रैक करेगा।यह अगले तीन वर्षों में 12 दिनों की नियमितता के साथ पूरे विश्व की मैपिंग करेगा, और यहां तक कि उन स्थानों को भी देखेगा जो अब तक अस्पष्ट थे।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- NISAR को वर्ष 2014 में हस्ताक्षरित एक साझेदारी समझौते के तहत अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया है।

- उम्मीद है कि इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकट-ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च किया जाएगा।यह उपग्रह कम-से-कम तीन वर्ष तक काम करेगा।

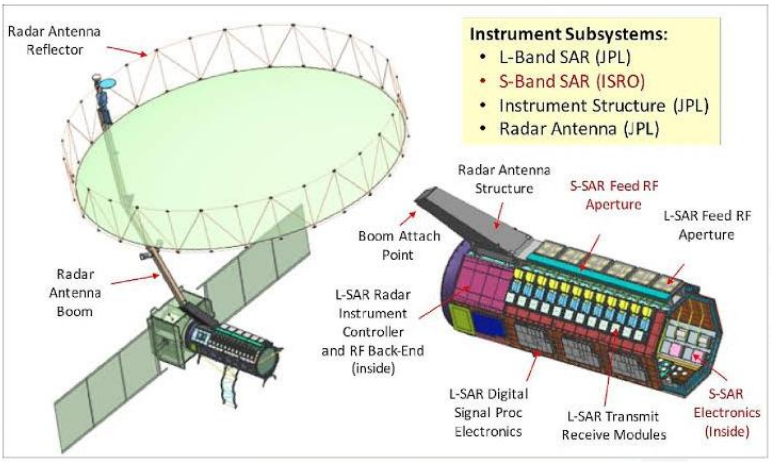

- यह एक निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit -LEO) वेधशाला है।यह 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्रण कर लेगा।
- यह 2,800 किलोग्राम का उपग्रह है जिसमें L-बैंड और S-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) उपकरण शामिल हैं, जिस कारण इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह कहा जाता है।
- नासा द्वारा डेटा स्टोर करने के लिये L-बैंड रडार, GPS, एक उच्च क्षमता वाला सॉलिड-स्टेट रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सब-सिस्टम प्रदान किया गया है, जबकि ISRO ने S-बैंड रडार, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) प्रक्षेपण प्रणाली तथा अंतरिक्ष यान प्रदान किया है।
- S-बैंड रडार 8-15 सेंटीमीटर की तरंगदैर्ध्य (Wavelength) और 2-4 गीगाहर्ट्ज़ की आवृत्ति (frequency) पर काम करते हैं। इस तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के कारण वे आसानी से क्षीण नहीं होते हैं। यह उन्हें निकट एवं दूर के मौसम अवलोकन के लिये उपयोगी बनाता है।

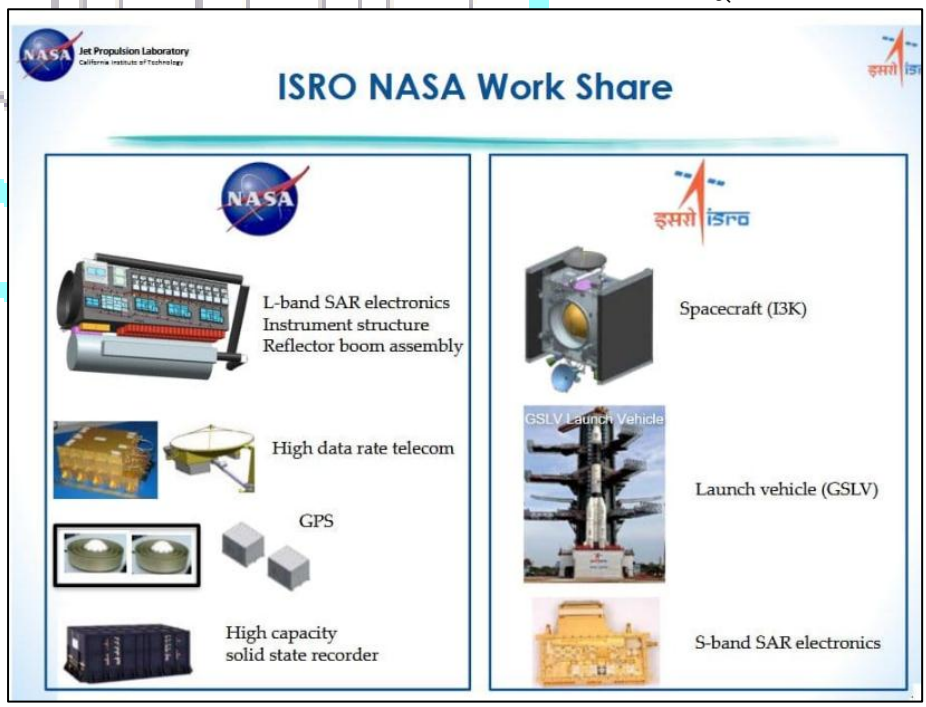

- इसमें 39 फुट का स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना है; रिफ्लेक्टर का उपयोग "उपकरण संरचना पर ऊपर की ओर फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रडार सिग्नल" पर केंद्रित करने के लिये किया जाएगा।
- SAR का उपयोग करके NISAR उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियाँ प्रस्तुत करेगा। बादलों का SAR पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, ये मौसम की स्थिति की परवाह किये बिना दिन और रात डेटा एकत्र कर सकते हैं।
- नासा को अपने विज्ञान संबंधी वैश्विक संचालन के लिये कम-से-कम तीन वर्षों के लिये L-बैंड रडार की आवश्यकता है। इस बीच इसरो कम-से-कम पाँच वर्षों के लिये S-बैंड रडार का उपयोग करेगा।

शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल थेरेपी

समाचार पत्रों में क्यों?

शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी-सेल (CAR-T) थेरेपी विश्व स्तर पर किये गए नैदानिक परीक्षणों के बाद अंतिम चरण के कैंसर रोगियों, विशेष रूप से लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया से पीड़ित रोगियों के उपचार में एक सफल तथा आशाजनक परिणाम के रूप में सामने आई है।

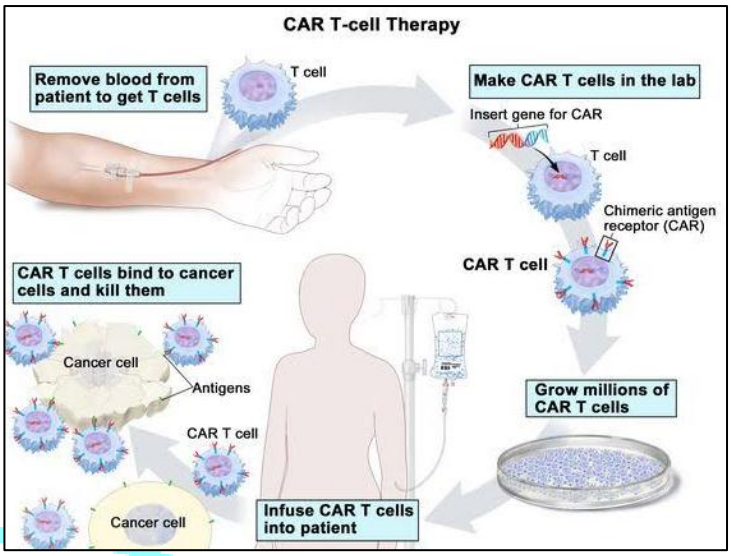

त्वरित मुद्दा?

- समय के साथ सर्जरी और रेडियोथेरेपी में सुधार हुआ है, हालाँकि प्रणालीगत चिकित्सा में विशेष रूप से प्रभावशाली प्रगति रही है, हाल ही में काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (Chimeric Antigen Receptor- CAR) T-सेल थेरेपी की सफलता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग विशिष्ट प्रकार के रक्त और लिम्फ नोड्स के कैंसर के रोगियों के लिए दूसरी या तीसरी पंक्ति के उपचार के रूप में किया जाता है।
- चिकित्सा की यह प्रकृति कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के लिए आवश्यक इंजेक्टेबल या मौखिक दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता को कम करती है।
- इसे कोशिका आधारित जीन थेरेपी के एक प्रकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने में मदद करने के लिए टी कोशिकाओं के अंदर जीन को बदलना शामिल है।
- CAR-T सेल थेरेपी में, ट्यूमर पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं के एक घटक टी-कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए उन्हें प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है।
- टी कोशिकाएं या टी लिम्फोसाइट्स एक

अन्य प्रमुख तथ्य?

T-सेल

- T-कोशिकाएँ, जिन्हें T-सेल लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएँ हैं जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं।
- T-कोशिकाएँ कोशिका-मध्यस्थ प्रतिरक्षा में शामिल होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे शरीर को विदेशी तत्त्वों, जैसे- वायरस, बैक्टीरिया और कैंसर कोशिकाओं जैसे असामान्य कोशिकाओं को पहचानने तथा प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद करती हैं।
- T-कोशिकाएँ प्रमुखतः दो प्रकार की होती हैं: हेल्पर T-सेल और साइटोटॉक्सिक T-सेल।
- जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सहायक T-कोशिकाएँ प्रतिरक्षा प्रणाली की अन्य कोशिकाओं की 'मदद' करती हैं, जबकि साइटोटोक्सिक T-कोशिकाएँ विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को नष्ट करती हैं।

प्रकार का ल्यूकोसाइट्स (श्वेत रक्त कोशिकाएं) हैं जो मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण हैं।

- प्रयोगशाला में टी-कोशिकाओं को संशोधित किया जाता है, जिससे ये कोशिकाएं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स (CAR) नामक विशिष्ट प्रोटीन को व्यक्त कर सकें।
- CAR प्रोटीन, टी-कोशिकाओं को ट्यूमर को प्रभावी ढंग से बाँधने और इसे नष्ट करने की अनुमति देता है।
- इन संशोधित कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से गुणा करने के लिए कंडीशनिंग के बाद रोगी के रक्त प्रवाह में वापस डाला जाता है।
- ये कोशिकाएं कैंसर के खिलाफ रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को सीधे सक्रिय करती हैं, जिससे उपचार अधिक नैदानिक रूप से प्रभावी हो जाता है, इसलिए इन्हें 'जीवित औषधियां' कहा जाता है।

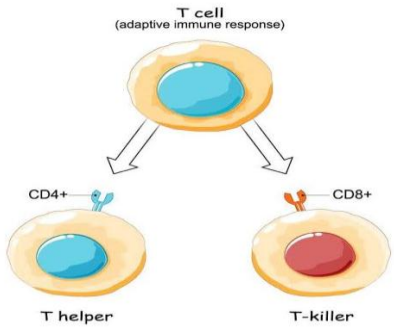

- CAR टी-सेल थेरेपी को ल्यूकेमियास (श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर) और लिम्फोमास (लसीका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले कैंसर) के लिए अनुमोदित किया गया है।
- यह प्रणालीगत चिकित्सा के अन्य रूपों की तुलना में उपचार को चिकित्सकीय रूप से अधिक प्रभावी बनाती है।

रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि

समाचार पत्रों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार(basis) अंक बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया।1 प्रतिशत, 100 आधार अंक के बराबर होता है।

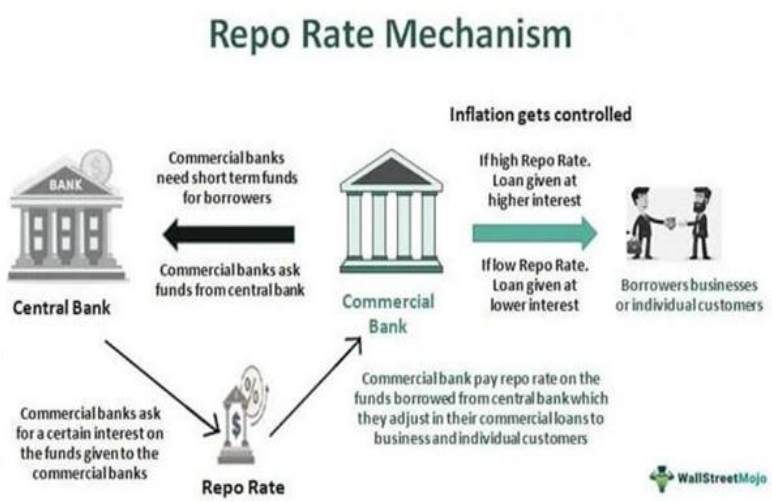

त्वरित मुद्दा?

- रेपो दर में वृद्धि के साथ ही स्थायी जमा सुविधा दर 6.25 प्रतिशत जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत हो गयी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिये दिए जाने ऋण पर जो ब्याज दर लागू करती है, उसे रेपो दर कहते है।
- रिज़र्व बैंक के सभी ग्राहक – बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार रेपो दर के तहत ऋण प्राप्त कर सकते है।
- इसके तहत ऋण लेने के लिये ग्राहकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है।

- बैंक, वैधानिक तरलता अनुपात(SLR) के तहत रिज़र्व बैंक के पास रखी प्रतिभूतियों का प्रयोग रेपो दर के तहत ऋण लेने के लिये नहीं कर सकते है।
- रेपो दर का निर्धारण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है।
- रेपो रेट बढ़ाने से बैंक रिजर्व बैंक से कम नकदी उधार लेते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, उम्मीद की जाती है कि ऐसा करने से महंगाई में कमी आयेगी।
- रेपो दर में वृद्धि का मतलब है, कि कर्ज महंगा होगा और मौजूदा ऋण की मासिक किस्त बढ़ेगी।
- रेपो दर बढ़ने के बाद बैंक, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन आदि कर्जों की दरें बढ़ा देते हैं, जिससे लोन लेने की लागत बढ़ जाती है।
- रेपो रेट में वृद्धि से उपभोग और मांग पर असर पड़ सकता है।
- रिवर्स रेपो दर:-वह ब्याज दर, जिस पर रिज़र्व बैंक एलएएफ के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों से चलनिधि को अवशोषित करता है।
- बैंक दर:-वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या फिर से भुनाने के लिए तैयार है।
  - बैंक दर दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है जो बैंकों द्वारा उनकी आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं (आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) को पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में उन पर लगाई जाती है।
  - बैंक दर को एमएसएफ दर के अनुरूप किया गया है और, जब एमएसएफ दर नीतिगत रेपो दर में परिवर्तन के साथ बदलती है तो वह स्वचालित रूप से बदल जाती है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

मौद्रिक नीति समिति

- मौद्रिक नीति समिति का गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिये 2016 में किया गया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में मौद्रिक नीति निर्माण को एक नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को सौंप दिया गया है।
- मौद्रिक नीति वह उपाय या उपकरण है है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मूल्य स्थिरता बनाये रखता है और उच्च विकास दर के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य रिज़र्व बैंक से होते हैं, जिनमें गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर तथा एक अन्य अधिकारी शामिल होता है।
- अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जिनका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तथा ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते है।
- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC) की एक वर्ष में 4 बैठकें होना अनिवार्य है, तथा बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होता है।
- समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हैं, और समान मतों की स्थिति में रिज़र्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है।

- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर:-वह दर, जिस पर रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों से ओवरनाइट आधार पर गैर-जमानती जमाराशियां स्वीकार करता है।
  - चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता साधन भी है।
  - एसडीएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक कम रखा गया है।
- 13)सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर:-वह दर, जिस पर बैंक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो का उपयोग कर रिज़र्व बैंक से ओवरनाइट आधार पर उधार ले सकते हैं।
  - यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के विरुद्ध एक सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है।
  - एमएसएफ दर को नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक अधिक रखा गया है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE